LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, February, 25, 1983/Phalguna 6, 1904 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCE

MR. SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of Shri V. N. Swami who was a Member of Second Lok Sabha during 1957—62 representing Chanda constituency of the then Bombay State.

An advocate by profession, Shri Swami functioned as Secretary and then Vice-President of Education, District Council (Board), Chanda during 1933—46.

Shri Swami was interested in labour welfare and international problems.

Shri Swami passed away at Chandrapur (Maharashtra) on 1st January, 1983 at the age of 78 years.

We deeply mourn the loss of this friend and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved family.

The House may stand in silence for a short while to express its sorrow.

The members then stood in silence for a short while.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Bombay Textile Workers' Strike

+

*82. SHRI MOHAMMED ISMAIL :
SHRI MADHAVRAO SCINDIA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what steps have been taken to settle the prolonged strike of textile workers of Bombay with the representatives of the unions conducting the strike;

(b) number of mills in which strike is still continuing; and

(c) what is the estimated loss to the industry, labour and the country, including loss of foreign exchange which could be earned through exports?

THE MINISTER OF COMMERCE AND OF THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c). The Government of India and the Government of Maharashtra have on many occasions appealed to the striking workers to return to work on the understanding that their genuine problems would be looked into. At the instance of the Government, the millowners have agreed to pay a recoverable advance of Rs. 1,500 per worker and interim relief of Rs. 30 per month. The Government of India have constituted a Tripartite Committee headed by a retired Chief Justice of the Bombay High Court to go into the problems of the workers in the Textile Industry.

2. All the textile mills in Bombay have been and continue to be affected in varying degrees by the strike.

3. The estimated loss on account of the Textile Workers Strike in Bombay is as under:—

(i) Estimated loss of production upto 31-1-1983	1083 million metres
(ii) Estimated loss of wages upto 31-1-1983	Rs. 180 crores.
(iii) Estimated loss of foreign exchange upto 31-1-1983 is roughly.	Rs. 200 crores

The loss to the country cannot be estimated since a number of ancillary industries and the trade have also been affected by the Strike.

श्री मोहम्मद इस्माइल : मेरा यह कहना है कि मैंने पहले कंसलटेटिव कमेटी में यह सवाल उठाया था। फिर मैंने यहां 22 तारीख को लेबर मिनिस्ट्री में यह सवाल किया था। 22 तारीख को यहां आया था। उसके बाद मुझे चिट्ठी भेज कर यह कह दिया गया कि यह सवाल लेबर मिनिस्ट्री से कामर्स मिनिस्ट्री को ट्रांसफर हो गया है और 25 तारीख को इसका जवाब आयेगा।

आज 25 तारीख को मैंने जो मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट देखा है उसमें वही पुरानी बातें कही गयी हैं कि हमने एक कमेटी बना दी है और ऐसा किया है। यह वही पुरानी बातें चल रही हैं जो कि पहले चल रही थीं। वर्करों के बारे में गवर्नमेंट ने एक प्रेस्टिज इशू बना लिया है। दुनिया में इतनी लम्बी स्ट्राइक कहीं नहीं हुई है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसको लाइटली क्यों ले रही है? क्यों इसकी जवाबदेही लेबर मिनिस्ट्री पर नहीं है? कामर्स मिनिस्टी कह रही है कि हमने कमेटी बना दी है! कमेटी ने अब तक क्या किया है? अगर टैक्सटाइल इंडस्ट्री को मोडरेनाइज करना है तो इसका फैसला पहले आप करो।

अध्यक्ष महोदय : सवाल करिये, साहब।

श्री मोहम्मद इस्माइल : आपने जो कमेटी बनायी है, उसका तमाम सेन्ट्रल ट्रेड यूनियंस ने बायकाट किया है। उन्होंने कहा है कि हम कमेटी में नहीं रह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिये।

श्री मोहम्मद इस्माइल : सवाल का जवाब दें तो सवाल करूं। आप मेरा सवाल सुन लीजिये। आपने जो टैक्सटाइल मिल के मजदूरों का तमाशा बना रखा है, आप उसकी जिन्दगी के साथ खेल रहे हैं....

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिये, लेक्चर मत दीजिये।

श्री मोहम्मद इस्माइल : आपने जो यह कमेटी बनायी है, उसने क्या रिकमेन्डेशंस किये हैं? क्या तमाम ट्रेड यूनियंस ने जिनको आपने उसमें नोमिनेट किया था, उसमें काम करने से इंकार किया है? क्या यह सही बात है?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो पुरानी चीजें थीं वही सदन के समक्ष रखी गयी हैं, और कोई नया प्रयास नहीं हुआ है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि यह जो कमेटी बनाई गई है उसकी बैठकें शुरू हो गई हैं, और जो उसकी बैठकें हैं 11 नवम्बर, 27 दिसम्बर, और फिर 27 और 28 जनवरी को यह कई बैठकें हुई, जिसमें महत्व की चीज यह है कि बदली वर्कर्स के लिए एक सब कमेटी बना दी गई जो बदली वर्कर्स के बारे में गहराई में जायेगी। एक कदम इस बारे में आगे बढ़ा है। यही नहीं जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री

दादा पाटिल हुए और कुछ ऐसा मौका रहा कि उसी समय मैं भी आया, उनसे तत्काल सम्पर्क करके इसके बारे में कोई हल निकाला जाये इसके लिये मैं उनसे सम्पर्क में रहा । और आपको जानकारी होगी कि कोई अहं पर, गो या प्रेस्टीज पर हम लोग नहीं खड़े रहे । श्री दत्ता सामन्त से दादा पाटिल की बात हुई है, और कल रात मैंने दादा पाटिल से बात की । वह इन्टीरियर में गये हुए थे । वह 27 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं उस पर आगे कदम उठाया जायगा । यह निश्चित जानें कुछ भी हो जहां तक श्रमिकों और मेहनतकशों का सवाल है हम लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी 1 साल पीछे रहेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी 13 महीने पीछे रहेंगे ।

श्री मोहम्मद इस्माइल : प्रेस्टीज इश्यू तो बनाया ही हुआ है । वर्किन्स क्लास के मामले में उनसे कनफ्रन्टशन की आपने एक नीति बना ली है। 13 महीने स्ट्राइक को हो गए हैं । अगर यह प्रस्टीज इश्यू नहीं है तो कैसे इतना लम्बा समय हो गया । यह इसी वजह से है । श्री दत्ता सामन्त जो वहां की स्ट्राइक का लीडर है यह आपका प्रेस्टीज इश्यू ही है कि चीफ मिनिस्टर मिलते हैं, सब मिलते हैं, मगर एक साथ बैठ कर उनकी मीटिंग में नहीं मिलना चाहते हैं । यह प्रेस्टीज इश्यू नहीं है तो क्या है ? कब तक यह चलेगा ? प्रोडक्टिव फोर्सेज के साथ कनफ्रन्टेशन का नतीजा यह हुआ कि 200 करोड़ रु० फौरेन एक्सचेंज का लौस हो गया । यह प्रस्टीज इश्यू नहीं है तो और क्या है ? यह नेशनल लौस हुआ कि नहीं ? आप कहते हैं कि सरकार ने इसको प्रेस्टीज इश्यू कभी नहीं समझा, जबकि एक तरह से प्रेस्टीज इश्यू का ट्रायल हो रहा है सिर्फ इसलिए कि स्ट्राइक लीडर से बात नहीं करेंगे । मैं यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो स्ट्राइक लीडर्स हैं डायरेक्ट उनकी मीटिंग बुलाकर आप उनसे मिलना चाहते हैं कि नहीं और इसका फैसला हो सके, इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं ? अगर प्रेस्टीज इश्यू नहीं है तो आप इस पर तैयार हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो जवाब आ गया उनका पहले ही । आप बिना वजह टाइम जाया कर रहे हैं ।

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: So far as the Government is concerned, it has always the interests of the labour at heart. Let it not be forgotten that we have taken over 115 mills just for the cause of labour. That has been our stand all through and we will continue to have before us the interest of labour. We have been very clear on that. So far as the question of prestige in meeting people is concerned, what to speak of Datta Samant, any person who is interested to have this issue resolved, in which so much suffering has come to the working class, I am ready to greet him which open hands, sit with him and talk. But, at the same time, I would appeal to people who stand on prestige and do not want to go to the tripartite Committee, they should also have a scrutiny of their ego. Let us not dismantle the forums of dialogue, because that is the essence of democracy.

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : अध्यक्ष महोदय, मिल-मालिक और मिल-मजदूरों के बीच का जो विवाद है, उस पर सरकार की जो भूमिका है, उसको यहां पर मंत्री महोदय ने स्पष्ट करने की कोशिश की; लेकिन उसमें कोई समाधान की बात नहीं है । चूंकि 13वां महीना चल रहा है और हकीकत यह है कि आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया है; मनमाने ढंग से एलान किया है । वहां मुख्य मंत्री, जो भी रहे, अपने-अपने एलान

करते रहे, लेकिन उससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। मंत्री महोदय मिल-मालिक और मजदूरों के बीच में जो विवाद है, उसको एक क्षण के लिए बाजू में रखें और बम्बई में जो नेशनल टैक्सटाइल मिलें हैं, जिनमें 35 हजार मजदूर काम कर रहे हैं, उसके बारे में जो भी आपकी ठोस योजना है, उसको अमल में क्यों नहीं लाते हैं? दूसरे, क्या यह सही नहीं है कि उन मिलों के मजदूरों ने अपने अपने स्तर पर कमेटी बनाकर काम पर वापिस गए, तब टैक्सटाइल मिल के मैनेजरों के मजदूरों को काम पर चढ़ने से रोक दिया? जो अन्दर लिए गए, उनको बिना किसी नोटिस के डिसमिस कर दिया। इस तरह से सैकड़ों मजदूर काम पर चढ़े हुए रास्ते पर फैंक दिए गए। जब यह मसला, जो आपसे पहले मंत्री थे, उनके सामने यूनियनों की ओर से पेश किया गया, तो वह पत्र सीधे मैनेजरों के पास भेजा गया। मैनेजरों ने कहा कि मंत्री महोदय दिल्ली में चाहें जो करें, लेकिन यहां हम मालिक हैं और हम तुम्हें सबक सिखायेंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन तीनों बातों पर अपनी स्पष्ट भूमिका सदन के सामने रखेंगे?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, भूमिका तो शुरू होती है, जब माननीय जार्ज साहब इन्डस्ट्री मिनिस्टर थे... (व्यवधान)...ऐसी जल्दी क्या है। आपको याद होगा....

PROF. MADHU DANDAVATE: This is Prime Minister's style, for every-thing is referred to the Janata Party.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दंडवते जी मैं आपको नहीं समेट रहा हूं। मैं केवल जार्ज साहब को कह रहा हूं।

प्रो. मधु दण्डवते : हमारे साथी हैं। (व्यवधान)....

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : जो समझौता 1979 में मिलओनर्स आर. एम. एन. एस. में है, वह आपके ही मंत्रित्वकाल में हुआ, जिसके विरुद्ध यह चीज उठाई जा रही है।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : क्या चीज हुई थी?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो एग्रीमेंट 1979 से 1984 तक हुआ, वह आप के ही काल में हुआ था और मेरे खयाल में उस पर आप की ही संस्तुति रही होगी जहां तक एन. टी. सी. मिल्स का सवाल है और सुझावों के कार्यान्वयन का सवाल है, एन. टी. सी. मिल्स पूरे उद्योग से भिन्न नहीं की जा सकती है। एक ट्री-पार्टाइट कमेटी बना दी गई, जिस का चेयरमैन एक जज को बनाया गया, तो कहीं पर ठहराव तो होना चाहिए, कहीं पर हम अपनी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में विश्वास ठहरायेंगे या सबको संदिग्ध देखते रहेंगे। उच्च न्यायालय का व्यक्ति, जो समिति का चेयरमैन है, वह सरकार से परे है, तो मेरे खयाल में सारी टैक्सटाइल मिल्स, वर्कर्स की बदली, वेजेज और हाउस रैंट एलाउन्स, ये सारी चीजें उसी परिप्रेक्ष्य में आती हैं। जहां तक मजदूरों के वापिस आने की बात है या कोई पत्र जाने की बात है, उसको मैं अवश्य देखूंगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि यहां पर मजदूरों के हित में जो सरकार फैसला करेगी, उस फैसले के कार्यान्वयन को किसी व्यक्ति विशेष के हित को न देखते हुए, मजदूरों के हित में करेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप देख लेंगे।

SHRI NIREN GHOSH: The strike has continued for fourteen long months. The strike started last year when it was declared a year of productivity. The atti-

tude taken by the Government was to teach a lesson to the workers at any cost. This has, therefore, become a single biggest blot on the policy of the Government of India. Is it a fact that Rashtriya Mill Mazdoor Union, the so-called recognised union has completely lost the confidence of the working class—textile workers of Bombay. You are trying to prop up that union. You are trying to teach the workers a lesson. That is why you have not been negotiating to settle the dispute. That is why you have been trying to drag this matter on for the last fourteen months.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: There is no question of having a confrontation with the working class or the workers. I assure you that we are not only interested in settlement with the workers but also that the workers should come and work: they should come with honour and in an honourable fashion.

So far as the RMMS is concerned, there is a statutory provision in law under which it is a recognised union. Even the industrial court has recognised it. That is the position to-day. We have to act under the law of the land. That is how in a democratic set up certain things function and I think having worked under that ambit....

SHRI SAMAR MUKHERJEE: The workers do not recognise but you recognise Them. Is that democracy? You talk of democracy!

PROF. MADHU DANDAVATE: That is antipeople democracy.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Well, that will take us into greater political debate if we start a debate on democracy. But I am letting you know what the provisions are. I want to assure the hon. Member that while this is the prevailing law... (*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Mr. Mukherjee, no interruptions like this please.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: This is monopolists' democracy. They should not talk of democracy.

SHRI SUNIL MAITRA: Do you recognise a minority union? Is this law?

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, I seek your protection to at least express myself.

MR. SPEAKER: Yes, you will have that.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: I want to assure the House, whatever may be the inscriptions in the law book, but when it comes to the interest of the working class, coma, full stop, dash and even brackets will not hold us acting on their behalf. This I can assure the hon. Members.

SHRI SUNIL MAITRA: Do not indulge in demogogue. For the last fourteen months you are... (*Interruptions*).

SHRI K. RAMAMURTHY: This Bombay strike has been going on for the last fourteen months. I should say it is unfortunate. We must view this strike in the right perspective. The demand were submitted by Dr. Dutta Samant. At that time the opposition trade unions never agreed for these demands. (*Interruptions*).

Pending the agreement, this demand was submitted by Dr. Dutta Samant. (*Interruptions*).

With long demands, some how or the other the workers also went on strike. Pending agreement, Government appointed Tripartite Committee to hold a meeting and to solve the question. The people who are now advocating things and ask for a meeting....

MR. SPEAKER: You do not reply to these things.

SHRI K. RAMAMURTHY: I am not reflying. why should I reply? Inspite of this, the trade union did not attend tripar-

tite meeting. Now they are talking of mutual negotiations and discussions. Moreover, pending agreement, this Government has announced certain advance payable to the workers. That was also not...

MR. SPEAKER: What is the question?

SHRI K. RAMAMURTHY: I would now ask the hon. Minister whether it is a fact that now more than 60 per cent of the workers have turned up to their work and if proper protection is provided 100 per cent workers will be there. I would like to know whether he will ensure protection?

MR. SPEAKER: He should have put the question straight-away.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: The protection will be given.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Sir, the replies to the questions are expected to be unambiguous. Now, the hon. Minister has said in the earlier portion of his reply that since his advent to the Ministry and the advent of Dada Patil to the Chief Ministership of Maharashtra, both of them are trying to settle the strike by meeting anybody who can help including Dr. Datta Samant. Later on, he has said that they are bound by the law, that is Bombay Industrial Relations Act, which recognises only the Rashtriya Mill Mazdoor Sangh as the representative Union and therefore they cannot ignore that.

Thirdly the committee is also sitting—the tripartite committee minus the major unions which have refused to be party to it—while the strike is going on. I want a clear reply from him. May I take the House to understand that now in their efforts to bring about a settlement, they will not refuse to talk to the leaders of the strike and they will not go on saying that the B.I.R. Act, is a legal impediment to that process? It should be clearly stated. The workers also would like to know.

Lastly, in his capacity as the Minister of Commerce, I would like just to ask him. In this statement, he has said that there has been a loss of 1083 million meters of cloth due to this strike. I would like to know what is his explanation for the fact that inspite of the big loss of production, there is apparently no shortage of cloth in the market? Is it his opinion or not that there is no shortage of cloth in the market although the biggest textile production centre is closed for 14 months and does it not show that the off-take of this cloth at the very prices at which it is being sold is not affected because the majority of people in our country—the ordinary consumer any how--has not got the capacity to buy at a high price? That is why, there is no shortage.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: Sir, answers to unambiguous questions also, should be the same. I am thankful to the hon. Member because he has put a very precise question.

So far as being bound by law is concerned, so long as the law exists, we are bound. But we are the people who frame the statute and I assure you that they shall not become fetters, if public interest demands.

SHRI INDRAJIT GUPTA: After 14 months of strike, the public interest is demanding something.

SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH: So far as meeting of the Tripartite Committee and other efforts are concerned, when the problem is of a human dimension, it is appropriate that we may open all channels to solve the problem. There is no conflict between the committee and the dialogue. The Chief Minister who is there to take care of the State to have a dialogue with it is absolutely not out of place.

So far as the question that despite the production of cloth being affected and the prices remaining the same is concerned, I agree with the hon. Member that there is a sluggishness of demand and that is the reason why prices have not gone up and not because high prices are there. That cannot be possible.